RAJYA SABHA

Wednesday, the 17th July, 1991/26 Asadha, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Kidnappings and abductions by militants in Kashmir

*61. SHRI MAHENDRA PRASAD:†
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether kidnappings and abductions for ransoms, otherwise and selective killings by militants have lately been on the increase in J&K.

(b) if so, what are the details of such incidents during the period from April to June,1991 and the comparative figures for the preceding quarter; and

(c) what special measures have been initiated for resolving the problem since change of Government at the Centre?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS(SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of House.

Statement

The terrorists violence including abductions, killings and targetted attacks on security forces continue to be of serious proportions.

During the quarter April to June, 1991, of 88 persons abducted. 12 were killed by terrorists. 57 Security Force personnel and 98 persons also lost their lives in terrorists actions during this quarter. In the preceding quarter, January to Mrach, 1991, of 66 abducted, 19 persons were killed by terrorists; whereas 57 Security Force personnel and 81 persons lost their lives.

Besides stepping up vigil on the border, Government of J & K has identified vulnerable pockets and active gangs for gearing up anti-terrorists operations, organising Naka ambushes and effective deployment of para-military forces in the affected sensitive pockets. Day and night patrolling in vulnerable areas, raid on hideouts of terrorists and extortionists have been intensified. Intelligence has also been strengthened. In addition to continuing the stringent measures against the terrorists, it is also proposed to set up People's Committees in the State to bridge the gap between the Government and the people and to enlarge employment opportunities for the youth.

SHRI MAHENDRA PRASAD: Sir, I would like to know whether the Government proposes to evolve a political solution including offer of a constructive economic package to the youth of Kashmir, through discussions and dialogue with political leaders and representatives of the people of the State including those who have fled form the valley. If so, may I know what steps have been taken and are being taken in this matter?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, so far as political discussion with some of the people who have some say in the Kashmir Valley is concerned we have taken up this issue. I have been able to discuss with two or three of them. I can't possibly say, but still I have a belief that they have a definite influence on the valley, and that is why I thought that we have to make a beginning for a political discussion We have already done it. So far as the economic package is concerned, that matter will have to be considered in greater detail in consultation with the Finonce Ministry.

SHRI MAHENDRA PRASAD: Sir, one part of the question has not been answered by him. So many people

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Mahendra prasad.

have left Kashmir, have gone out of Kashmir. Have you talked to them?

SHRI S. B. CHAVAN: I do not know whether the honourabe Member is referring to the people who have come down to Delhi and also to Jammu. If that be the position, some of them did come to me and I have discussed with them also.

SHRI MAHENDRA PRASAD: Sir, may I know whether the Government has lately been considering revival of the so-called Farooq formula for a political settlement of the Kashmir issue? If so, what is the Government's stand on the various proposals in the Farooq formula including revival of the dissolved Assembly?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, we are having discussions about the whole thing, and I think it will be premature to give any publicity to what we are discussing.

डा. रत्नाकर पाण्डेय माननीय सभापति जी, गृह मंत्री जी ने जो हमारे संयुक्त प्रश्न का जवाब दिया है, उसमें कहा गया है कि "जनवरी से मार्च, 1991 के दौरान आतंकवादियों द्वारा 66 व्यक्तियों का अपहरण किया गया और 19 व्यक्तियों की हत्या की गई, जबकि सुरक्षा बल के 57 कर्मियों और अन्य 81 व्यक्तियों की जाने गई।"

मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं या आतंकवादियों द्वारा जिनका अपहरण किया गया है, उनका नाम क्या है? कितने उनमें से अब तक वापिस आ चुके हैं? जिनकी हत्या हुई है उनके लिए आपकी सरकार ने क्या किया है?

प्रश्न के अंत में आपने कहा है कि "आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को जारी रखने के अलावा सरकार और लोगों के बीच की दूरी को कम करने और युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य में लोक समितियों की स्थापना करने का प्रस्ताव भी है।"

यह जो राज्य में लोक समितियां प्रस्थापित करेंगे, उसमें अंनएम्प्लायमेंट मूल समस्या है कश्मीर की, उसमें कितने अनएम्प्लायड एजुकेटड और अनएजुकेटेड लोगों को काम देंगे, उसमें टर्म्स आफ रिफरेंस, सी०आर० क्या हैं? क्या वे तय करेंगे? कैसी कमेटी बनाएंगे उन लोगों के बारे में जो जेल में अभी बंद हैं और हथियार डाल रहे हैं, हृदय परिवर्तन जिनका हो रहा है और आतंकवाद से अलग हटकर के राष्ट्रीय धारा में आ रहे हैं? कितने ऐसे लोगों ने अब तक समर्पण किया है और उनको रोजी रोटी देने के लिए आपने क्या किया है? 19 जनवरी, 1990 को कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की जो सरकार थी और जो डैमोक्रेसी रिस्टोर कर यही थी उसके बाद अभी लगभग तीन सवा तीन साल तक वहां चुनाव होने हैं, तो क्या पुरानी असेंबली को संचालित करने के लिये क्योंकि आपकी सरकार थी और दूसरी सरकार जब सत्ता में आयी तो उसने असेंबली को यकायक भंग कर दिया और अब फिर हमारी कांग्रेस की सरकार आयी तो आपने असेंबली को रिवाइव करने के लिये अब तक कोई ठोस उपाय किये हैं और यदि नहीं किये हैं तो कब तक इस सदन में कोई प्रस्ताव लेकर आयेंगे और वक्तव्य देंगे कि हमारी कांग्रेस की सरकार जो सोनिया गांधी की कृपा से आज आसीन हुई है वह कश्मीर में फिर से जनतंत्र को बहाली करने जा रही है?

डा० बापू कालदाते : उसके बगैर चलता ही नहीं?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : नहीं चलता, देश नहीं चलेगा उसके बगैर.... (**व्यवधान**)

डा० बापू कालदाते : नहीं, वह अलग बात है.... (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वी.पी. सिंह से नहीं चलेगा... (**व्यवधान**)

एक सम्मानित सदस्य : इसमें आपको क्या आपत्ति है?

एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इतने सवाल पूछे हैं कि उसके ऊपर एक बावजह डिस्कशन खड़ा हो सकता है। इसलिये उनके सारे सवाल तो मुझे याद रखना मुश्किल है। जितने सवाल मेरी समझ में आये और याद रख सका हूं उसके हद तक मैं कह सकता हूं। पहले आखरी सवाल का जवाब देता हूं। यह बात सच है कि ... (**व्यवधान**)

एक सम्मानित सदस्य : दुबारा पूछ लेंगे सवाल?

श्री एस. बी. चव्हाण : नहीं नहीं, आपको जो अधिकार है वह मेरा अधिकार नहीं है। वह अध्यक्ष महोदय का अधिकार है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आपकी इच्छा होगी तभी अध्यक्ष जी एलाऊ करेंगे।

श्री एस. बी. चव्हाण : खैर, आखरी सवाल का जवाब मैं पहले आपको देता हूं। वहां की जो डयूली इलैक्टिड गवर्नमेंट थी उसको करीब-करीब सुपरसीड किये हुए दो साल होते हैं। वहां पर गवर्नर की तरफ से और प्रेजीडेंट की तरफ से फिर प्रेजीडेंट रूल भी एक्सटेंड हुआ। यह सारा मामला आज हाईकोर्ट में है और जो भी हाईकोर्ट का फैसला होगा उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा।

कितने लोगों को छोड़ा गया है अगर आप इनके नाम चाहते हैं तो जो फॉरेन नेशनल थे उसकी आपको जानकारी होगी। जो स्विस पकड़े गये थे उसमें उनका कहना है कि उनका आपस में समझौता हुआ और उसके अंदर उनको मौका मिला और वह भागे-दौड़े। 20-25 किलोमीटर तक पैदल वह लोग वहां से भागे। दूसरी तरफ उन लोगों ने जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा था, वे कहते हैं कि हमने इनको भागने की इजाजत दी थी। अब सच कौन है, यह मेरे लिये बोलना मुश्किल है। छोड़ने के तीन-चार और जो केसेज हैं आपको उनके नाम मालूम ही हैं। मुफ्ती साहब की लड़की को छोड़ा था। सोज़ साहब की लड़की को छोड़ा था। ऐसे 3-4 लोग हैं जिनको छोड़ा है। दूसरों के नाम अभी मेरे पास नहीं है।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : लोक समितियों की बात मैंने की थी। अपने जवाब में कहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये राज्य में लोक समितियों को स्थापना करने का प्रस्ताव भी है। इस पर भी माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी प्रकाश डालें कि क्या चीज है?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह लोक समिति इसलिये बनायी जायेगी कि वहां पर जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता है उस वक्त तक वहां पर लोगों के अंदर एक किस्म का लएजां कायम होना चाहिये। वहां गवर्नर और उनके जो एडवाइजर्स काम करते हैं, दोनों में लाएज लाने के लिये हम यह कमेटियां स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी सलाह से वहां पर जो भी काम होता है वह आगे हम करें।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया : ऑनोरेबिल होम मिनिस्टर साहब, क्या हुकूमत इस बारे में गौर करेगी कि जो लोग जेलों में बंद हैं वे काफी तादाद में हैं और कश्मीर में एक सही मैसेज भेजने के लिए कि जो उनमें निर्दोष हैं, उनको छोड़ देने पर सोच विचार करेगी और उस बारे में कोई ऐसी कमेटी बनायेगी जिसमें मुखतलिफ सियासी जमातों के नुमइंदे हैं, जो उनके केसेज को रिव्यू करें ताकि वे लोग जिनके खिलाफ कोई टैरोरिज्म का इलजाम नहीं है या जो आतंकवाद को छोड़ चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाये ताकि वे लोग नेशनल धारा में शामिल हो सकें। इससे वादिये कश्मीर में और सारी रियासतों में एक अच्छा मैसेज जायेगा और वहां के हालात में बेहतरी पैदा हो सकेगी। जहां तक कमेटी के कांस्टीट्यूशन का सवाल है, मैं उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं कि

क्या आप कमेटी का गठन इस प्रकार करेंगे कि उसमें सिवासी नुमाइंदों को भी रिप्रैजेंटेशन हासिल हो सकेगा और क्या इसकी कोई ऐसी पावर्स होंगी कि उन पावर्स के अख्तियार से वह काश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए कोई काम कर सकेगी ?

†[شری شبیر احمد ۔ الویہ : آنریبل ہوم منسٹر صاحب کیا حکومت اس بارے میں غور کریگی کہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں اور کشمیر میں ایک صحیح سیسیج بھیجنے کیلئے کچھ جو ان میں نردوش ہیں انکو چھوڑ دینے پر سوچ وچار کریگی اور اس بارے میں کوئی ایسی کمیٹی بنائیگی جسمیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں - جو انکے کیسیز کو دیویوز کریں تاکہ وہ لوگ انکے خلاف کوئی اوور ایکٹ کا الزام نہیں ہے یا جو آتنکواد کو چھوڑ چکے ہیں - انکو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ لوگ نیشنل دھارا میں شامل ہو سکیں - اس سے وادی کشمیر میں اور ساری ریاستوں ایک اچھا سیسیج جائیگا - اور لاء اینڈ آرڈر کے حالات میں بہتری پیدا ہو سکیگی - جہاں تک کمیٹی کے کانسٹی ٹیوشن کا سوال ہے میں اس سمبندھت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کمیٹی کا گٹھن اس پرکار کرینگے کہ اس میں سیاسی نمائندوں کو بھی ریپرزینٹیشن حاصل ہو سکیگی - اور کیا اسکی کوئی ایسی پاورس ہونگی کہ ان پاورس کے اختیار سے وہ کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے کیلئے کوئی کام کر سکیگی -]

श्री एस. बी. चव्हाण : ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल पूछे हैं उनमें से पहला सवाल तो इस बारे में है कि जो कमेटी बनेगी उसमें सिवासी लोगों को रिप्रैजेंटेशन दिया जाएगा या नहीं। इसके बारे में मैं सोचूंगा। इसमें अगर पोलिटिक्स आ गई तो उसकी वजह से हालात बेहतर बन सकते हैं, या खराब हो सकते हैं इस बारे में जब तक मैं अच्छी तरह से विचार नहीं कर लेता तब तक में कोई कमिटमेंट हाउस में नहीं करना चाहूंगा।

दूसरे, मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं कि कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ अगर कोई एविडेंस न मिले तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। काफी लोगों को हमने "टाडा" के अंदर छोड़ा है।

The number of persons arrested under TADA was about 2,360 in 1990 and 1,249 in 1991. The actual number of those who remained in custody was 1,766 in 1990 and 1,011 in 1991. Other figures are also available with me and if the hon. Member is interested I will be able to give. But, I must say that I am in full agreement with the hon. Member that if there are no serious charges or if no evidence is coming forth, then, of course, there is every reason to release them.

श्री सत्यप्रिय गौतम : माननीय सभापति महोदय, अभी तक अनेक राज्यपाल कश्मीर में बदले जा चुके हैं और राज्यपालों के सलाहकार भी बदले जा चुके हैं लेकिन

†Transliteration in Arabic script.

स्थिति बराबर बिगड़ती चली जा रही है। हमारे योग्य साथी सलारिया साहब ने एक सुझाव दिया कि यह कमेटी उन केसेज़ को रिव्यू करे जिनमें निर्दोष लोग फंसाए गए हैं। माननीय, कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि इसका कोई पोलिटिकल सैटलमेंट होना चाहिए तो इस सुझाव के पीछे शायद उनकी मंशा यही रही होगी कि वहां पर विधान सभा को रिस्टोर कराया जाए, चुनाव कराए जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब एडवाइज़र टु दि गवर्नर और खुद गवर्नर भी इसमें कामयाब नहीं हो सके तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मुख्तलिफ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सलाह और सुझाव वहां के गवर्नर लें और उनके अनुसार फिर आगे का कोई निर्णय लें।

श्री एस. बी. चव्हाण : वहां जो गवर्नर हैं उन्होंने कई मर्तबा एम० पीज़ और एम० एल० एज़० को अपनी मीटिंगों के लिए बुलाया है और उनसे सलाह लेने की कोशिश की है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वहां लोकसभा के एम० पीज० तो हैं नहीं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : कुछ एम० पीज० राज्य सभा के हैं। सलारिया साहब वहीं के हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कुछ लोग इस्तीफा दे चुके हैं जैसे गुलाम रसूल मट्टू साहब इस्तीफा दे चुके हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपका कहना ठीक है कि ऐसे लोगों से सलाह लें लेकिन यह मामला सिर्फ सलाह से हल होने वाला नहीं है। शांति निर्माण के लिए जो करना जरूरी है वह हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वहां शांति भंग करने का काम पड़ोस के देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जाता है। इसलिए वहां के लोगों से सलाहमशविरा करने से यह मामला हल होने वाला है, ऐसा तो अभी तक दिखा नहीं है। हम इस समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे है। इसके लिए एक तो हमने डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी है और दूसरी तरफ हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है उनको भी हमने इस बात के लिए बाध्य किया है कि वे बड़ी सख्ती के साथ इन लोगों के साथ पेश आएं।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: We are moving from crisis to crisis in Kashmir. It is a continuous crisis without any end. When I listened to the Home Minister, he gives the impression that all things are being done to solve the crisis. But the crisis is not solved. I do not blame him. One happy development has taken place in the international forum—the European Parliament has taken cognizance of the situation in Kashmir. I appreciate it. But many terrorists have been arrested and they have been kept in custody. We have been hearing through the Radio and T.V. that many weapons have been captured and many types of information have been collected. May I know from the hon. Home Minister if he has collected various facts and various types of information from these people? Will he be able to evaluate these things and make a statement in the House?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I do not want to give any incorrect information to the House. I have frankly given the assessment of the situation to the House. At the same time, evaluation will have to be done and thereafter we will have to take a policy decision as to how we propose to deal with the matter. I must say things are pretty bad. I do not want to hide them from the House. The redeeming feature that I find in the entire situation is that in the Pakistain-occupied Kashmir the movement seems to be not in favour of Pakistan but for an independent State. But it does not give us any relief that way. So far as they are concerned, there might be a friction between the two groups who are trying to infiltrate

into our country. So far as we are concerned, whether they are for Pakistan or for an independent Kashmir, certainly it does not make much of a difference. We will have to deal with both of them. In the same manner, I don't think that we can afford to have any kind of lenient view towards those who are in favour of creation of an independent Kashmir.

SHRI VIREN J. SHAH: The Leader of the Opposition had asked about the arrests of a large number of journalists. You have not replied to that point.

SHRI S. B. CHAVAN: I require notice for that. I do not have the information now.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Sir, we have been given certain information about the other people having been killed without actually clarifying that they have been killed by the terrorists or they have been killed by the security forces. If they have been killed by the terrorists, have we got any figures of the terrorists, security forces and other civilians who have been killed because of certain incidents that might have occurred?

The second point I have is that we have been talking about having People's Committees. I would like to know from the Minister what sort of response we had from the people. Are they willing to sit in these Committees and expose the terrorists?

The information that I have gathered by talking to the various people—I have not visited that place—is that the people are extremely frightened of being found anywhere near the Government authorities or anybody. In fact, there are people who want to have their children taking up jobs but they are frightened of putting an application. I really like to know: Is there any hope of having these Committees? May I know from the Minister whether people have volunteered to serve in these Committees? May I know from the Minister whether they know that these Committees are trying to discuss matters with the Government on the one side and the public on the other?

SHRI S. B. CHAVAN: Regarding the first part of his question, the number of militants or susbversives apprehended on the border in 1990 was 1,303 and in 1991, 200. The number of person killed in terrorist violence in 1989-90 was 461 persons and in 1990-91, 175 persons. The number of security force personnel killed in 1990 was 135 and 56 in 1991, 94. On the second part of the question, I am in full agreement with the hon. Member that there is a fear psychosis and it is very difficult to persuade people in spite of the efforts that we have been making. The situation, as it is, really creates fear in the mind of people that if they try to associate themselves with any kind of activity of the Government, there is always the threat of their children being abducted or their being killed. I cannot deny the fact. But we will have to live with it for some time at least in order to find out how best we can find a solution to the problem.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Mr. Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister whether the increase in disparities of incomes of people in certain parts of the country is not responsible for the increasing violence and if so, what measures are proposed to be taken to reduce the disparities of incomes of people? Secondly, what are the steps being taken to restore employment to the traditional artisans whose emplnyment is being snatched away by the financiers of the mechanised industry because all these unemployed people are gathering and continuing to provide a fertile ground for terrorist and violent forces?

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, I am in full agreement with the hon. Member that there is a great disparity between the per capita income of Kashmiris and that of the rest of the country. That is why the Planning Commission are giving not only Plan

assistance but also non-Plan assistance. It was so when I was in the Planning Commission. I cannot say what the latest position about it is. But it was almost 110 per cent that we used to give, only with a view to see that in matters of development, they come on par with the rest of the country. That was the point of view we had.

Coming to the handicrafts that the hon. Member has referred to, there is still great demand for the handicrafts of Kashmir in spite of the mechanisation introduced. For example, there is tremendous demand for Kashmiri carpets because they have different designs and people, in fact, like very much Kashmiri Carpets. It is not that there is no demand for the same.

MR. CHAIRMAN: Question No. 62.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Mr. Chairman, Sir, I have one supplementary .

MR. CHAIRMAN: I have allowed one supplementary. Question No. 62.

Commission to Inquire into Assassination of late Rajiv Gandhi

*62. SHRI P. UPENDRA:†

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a Commission of Inquiry has been set up to inquire into the dastardly assassination of the former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, on 21st May, 1991 if so the terms of reference of the Commission;

(b) the progress made by the Commission as well as by the SIT in unearthing the conspiracy and by when the Commission is likely to submit its report; and

(c) whether the terms of reference of the Enquiry Commission have been revised; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A Commission of Inquiry was set up on 27.5.91 consisting of Justice Shri J. S. Verma, a sitting Judge of the Supreme Court of India. The terms of reference of the Commission are as under:—

(a) whether the assassination of Shri Rajiv Gandhi could have been averted and whether there were lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the individuals responsible for his security;

(b) the deficiencies, if any, in the security system and arrangements as prescribed or operated in practice which might have contributed to the assassination. The Commission may also recommend the corrective remedies and measures that need to be taken for the future with respect to the matters specified in clause (b) of the paragraph mentioned above. The Commission is to submit its Report within 3 months.

The Verma Commission of Inquiry has already issued a notice inviting from individuals, Associations, Organizations, Institutions, Authorities and all other persons acquainted with the subject matter of the inquiry to furnish to the Commission a statement of facts relating to the matters specified therein on or before 31st July, 1991, and wide publicity has been given to the above Notice.

The SIT has so far examined 189 witnesses, carried out searches at 33 places and arrested 12 accused persons. Further investigation is in progress and disclosure of any other information in this connection at this

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri P. Upendra.